

[2023] 6 एस. सी. आर 399

ए.

कामुकायी और ओआरएस. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। (2023 की सिविल अपील संख्या 3799) 16 मई, 2023
बी.

[सूर्या कान्ट और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

रेलवे अधिनियम, 1989-एस.123(ग) और 124-रेलवे यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच का तरीका) नियम, 2003 -आर. 7-मुआवजे का दावा-पीड़ित-मृतक प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और सिर कलम करने और दाहिने हाथ को काटने सहित गंभीर चोटें आईं-मृतक की मौत पर ही मौत हो गई-प्राथमिकी दर्ज की गई-पूछताछ रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से स्पष्ट रूप से पता चला कि मौत रेलवे की अप्रिय घटना का परिणाम थी-रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की गई थी-दावा न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलार्थियों एक अप्रिय घटना में मृतक की मौत को साबित करने में विफल रहे थे और वह वास्तविक यात्री नहीं था जिससे रेलवे मुआवजे के अनुदान के लिए उत्तरदायी था-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा-अपील पर कहा गया:एफ. आई. आर., जांच रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और नियम, 2003 के नियम 7 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आरोपों को देखने के बाद, एक अप्रिय घटना के संबंध में आरोप, जैसा कि दावा याचिका में कहा गया है, पूरी तरह से स्थापित और मृतक के बेटे एडब्ल्यू 1 की गवाही द्वारा समर्थित है-इसलिए, दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष जांच के दस्तावेजों और अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना हैं-जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या मृतक एक वास्तविक यात्री था, एडब्ल्यू 1 के नेत्रहीन बयान कि उसने वैध ट्रेन टिकट प्राप्त किया था और मृतक को दिया था, दावा याचिका में किए गए दावे की गवाही दी गई थी और यहां तक कि प्रतिपरीक्षा में भी, उन्होंने दोहराया है कि मृतक के लिए टिकट दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

भार का निर्वहन नहीं किया-इसलिए, रेलवे प्रशासन निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1. एफ. आई. आर.,** जाँच रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और नियम, **2003** के नियम **7** के तहत तैयार की गई जाँच रिपोर्ट के आरोपों के अवलोकन पर, एक अप्रिय घटना के बारे में आरोप, जैसा कि दावा याचिका में कहा गया है, पूरी तरह से स्थापित है और मृतक के बेटे एडब्ल्यू **1** की गवाही द्वारा समर्थित है। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष जांच के दस्तावेजों और डी. आर. एम. द्वारा **7.6.2017** पर स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना हैं और इसलिए ऐसे निष्कर्ष विकृत और निर्धारित हैं।[पैरा **17**] **[407-जी-एच; 408-ए]**

बी.

सी.

2. अब, इस मुद्दे पर लौटते हुए कि क्या मृतक एक प्रामाणिक यात्री था? इस संबंध में, मृतक के बेटे एडब्ल्यू **1** का मौखिक बयान, जिसने यात्रा के लिए एक वैध ट्रेन टिकट प्राप्त किया और इसे मृतक को सौंप दिया, रिकॉर्ड में है। ए. डब्ल्यू. **1** के बयान के अनुसार, दावा याचिका में किए गए कथनों की गवाही दी गई है और यहां तक कि जिरह में भी उन्होंने दोहराया है कि मृतक के लिए टिकट रुपये की राशि में खरीदा गया था। **10/-** और उसे स्टेशन पर भेज दिया। मृतक रेलवे स्टेशन पर गिर गया। दावा याचिका के उक्त कथन और स्टेशन मास्टर के बयान को घटना की तारीख पर पूछताछ अधिकारी द्वारा तैयार की गई पूछताछ रिपोर्ट यानी **27.9.2014** और जाँच अधिकारी, रेलवे पुलिस स्टेशन त्रिची द्वारा **14.11.2014** पर तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट से समर्थन मिलता है। उक्त रिपोर्टों को दिनांकित **7.6.2017** जांच रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है। अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक बोझ कि मृतक यात्री के पास एक वैध टिकट था, उक्त तथ्य को गलत साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन पर स्थानांतरित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ भी नहीं रखा गया है या रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि रेलवे प्रशासन ने मृतक यात्री के साथ वैध रेलवे टिकट नहीं होने का बोझ उठाया है, सिवाय इसके कि वसूली के दौरान टिकट नहीं मिला था। किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, रेलवे प्रशासन निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।[पैरा **18**] **[408-बी-एफ]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

401

कामुकायी और ओआरएस. बनाम.भारत और ओआरएस का संघ।

3. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि रीना देवी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह उचित संदेह से परे साबित होता है कि पीड़ित-मृतक की मृत्यु एक यात्री ट्रेन संख्या **5684** में यात्रा करते समय हुई एक अप्रिय घटना में हुई थी और वह एक प्रामाणिक यात्री था। दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल रूप से दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष विकृत हैं, इसलिए निर्धारित किए गए हैं। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, रेलवे अधिनियम की धारा **124 ए** और रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, **1990** में निहित प्रावधानों के अनुसार, अपीलार्थियों मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं। [पैरा **19**] [408-एफ-एच]

बी.

सी.

4. दावेदारों को मुआवजे की मांग करने का हकदार माना जाता है, लेकिन सुनवाई के दौरान, यह ध्यान में लाया जाता है कि दुर्घटना की तारीख के बाद और **25.7.2016** पर दावा याचिका दायर करने के बाद, क्षतिपूर्ति नियम, **1990** में **W. E. F. 01.01.2017** में संशोधन किया गया था। इसलिए, संशोधित नियमों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। अपीलार्थियों एक लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।

4,00,000-दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक **7** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज दर लागू करने के बाद, यदि अंतिम आंकड़ा रुपये से कम है। **8,00,000-**, तब अपीलार्थियों रुपये के हकदार होंगे।

8,00,000-। [पैरा **20,23**] [409-ए-बी; 411-ई-एफ]

डी.

ई.

भारत संघ बनाम रीना देवी **(2019) 3 एस. सी. सी. 572:[2018] 4 एस. सी. आर. 417;** यू. ओ. आई बनाम राधा यादव **(2019) 3 एस. सी. सी. 410:**

[2019] 1 एस. सी. आर. 741-पर निर्भर।

एफ.

जेट्टी नागा लक्ष्मी पार्वती बनाम भारत संघ **2011** एससीसी ऑनलाइन एपी **828**;
कामरुन्निसा बनाम भारत संघ **(2019) 12 एससीसी 391**; भारत संघ बनाम दिलीप और
अन्य

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2119-संदर्भित।

जी.

राज कुमारी बनाम भारत संघ **1992 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 96**; गुरचरण सिंह
बनाम भारत संघ **2014 एस. सी. सी.**

ऑनलाइन डेल **101-संदर्भित।**

एच.

402 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

ए.

संदर्भित निर्णय

[2018] 4 एससीआर 417

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

[2019] 1 एससीआर 741

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

(2019) 12 एस. सी. सी. 391

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

बी.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 3799।

2019 के सी. एम. ए. संख्या 2442 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

सेंथिल जगदीशन, सजल जैन, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सी.

अमरीश कुमार, शवोदीप रॉय, शेटी उदय सागर, विवेक नारायण शर्मा, श्रीमती अलका अग्रवाल, अमित शर्मा बी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. के. माहेश्वरी, जे.

डी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अपीलार्थियों द्वारा दायर सिविल विविध अपील संख्या 2442/2019 में मद्रास के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.03.2021 के फैसले से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि अपीलार्थियों किसी भी अप्रिय घटना को स्थापित करने में विफल रहे थे या मृतक एक प्रामाणिक यात्री थे, हालांकि रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ के विवादित फैसले को बरकरार रखते हुए, मुचामी @मुथुसामी की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। दोनों निर्णयों को चुनौती देते हुए, दावेदार/अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

ई.

एफ.

3. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले के तथ्य यह हैं कि मृतक-मुचामी @मुथुसामी (अपीलार्थियों 1 के पति और अपीलार्थियों 2 और 3 के पिता) को सरकारी अस्पताल, करूर में चिकित्सा उपचार के लिए जाने की आवश्यकता थी। वह अपने बेटे (अपीलार्थी 3) के साथ लालपेडुई रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसने करूर का रेलवे टिकट खरीदा और मृतक को सौंप दिया, जो करूर पहुंचने के लिए ट्रेन संख्या 56841-त्रिची इरोड पैसेंजर में सवार हुआ। जब ट्रेन महादनापुरम रेलवे स्टेशन पहुंची, डिब्बे में भारी भीड़ और ट्रेन के झटके के कारण, मृतक अप्रत्याशित रूप से प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच चल रही ट्रेन से KM 90/200-300 पर गिर गया और उसे सिर काटने और दाहिने ए को काटने सहित गंभीर चोटें आईं।

जी.

एच.

कामुकायी और ओआरएस. बनाम.भारत और ओआरएस का संघ। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

हाथ।मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।रेलवे पुलिस स्टेशन, करूर में एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, जाँच रिपोर्ट तैयार की गई थी और अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु रेलवे की अप्रिय घटना का परिणाम थी।सरकारी अस्पताल, करूर में किए गए पोस्टमार्टम से संकेत मिलता है कि मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगने और सिर के सिर काटने के कारण सदमे और रक्तस्राव था।दावा याचिका 25.07.2016 पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें मुआवजे की मांग की गई थी। आवेदन जमा करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 लाख रुपये।

बी.

4. प्रत्यर्थियों ने बचाव करते हुए इस दावे का विरोध किया कि मृतक एक वास्तविक यात्री नहीं था क्योंकि उसकी यात्रा का टिकट नहीं मिला था और घटनास्थल से केवल गुलाबी रंग की डिजाइन लुंगी और लाल रंग के अंडरवियर के साथ विकृत स्थिति में सफेद रंग की फटी हुई शर्ट बरामद की गई थी।जाँच रिपोर्ट के अनुसार, शव दाहिने कंधे के स्तर पर सिर कटा हुआ पाया गया था।कहा जाता है कि अगर मृतक चलती ट्रेन से गिर गया होता तो उसका शव रेलवे पटरी के बाहर नहीं मिलता।हालाँकि, चोटों की प्रकृति को देखते हुए, जैसा कि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मृतक की अप्रिय घटना के कारण मृत्यु के आरोप से इनकार किया गया था, इसलिए दक्षिण रेलवे किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

सी.

डी.

5. रिकॉर्ड से पता चलता है कि दावा याचिका कुछ देरी से दायर की गई थी जिसे दावा न्यायाधिकरण द्वारा 01.11.2016 दिनांकित आदेश के अनुसार माफ कर दिया गया था।दावा न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 1 के फैसले में दावा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थियों एक अप्रिय घटना में मृतक की मृत्यु को साबित करने में विफल रहे हैं और वह एक प्रामाणिक यात्री नहीं था जिससे रेलवे मुआवजे के अनुदान के लिए उत्तरदायी हो गया।दावा न्यायाधिकरण स्टेशन मास्टर डी. रविशंकर के बयान से प्रभावित था, जिनके सामने मृतक के बेटे की उपस्थिति में शव की तलाशी ली गई थी और उस समय शव के साथ यात्रा का टिकट नहीं मिला था।दावा न्यायाधिकरण ने स्केच मानचित्र और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है, जबकि अपीलार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

6. उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की सिविल विविध अपील संख्या 2442 दायर करने पर, यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया गया कि दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष विकृत नहीं हैं क्योंकि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं पाया गया था और अपीलार्थियों यह साबित करने में विफल रहे हैं कि मृतक की मृत्यु अप्रिय घटना का परिणाम है।

एच.

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

7. उन निष्कर्षों पर जोर देते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिकी, दिनांकित आई. डी. 2 और दिनांकित आई. डी. 1 की अंतिम रिपोर्ट पर भरोसा किया और तर्क दिया कि घटना रेलवे अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, "रेलवे अधिनियम") की धारा 123 (सी) (2) के तहत परिभाषित अप्रिय घटना का परिणाम थी। यह भी आग्रह किया जाता है कि दावा याचिका में किए गए कथन और दावेदार-अपीलकर्ता मणिकंदन (एडब्ल्यू-1) के बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उसने 10 रुपये का टिकट खरीदा था और लालपेडुई से करूर तक ट्रेन संख्या 56841 में यात्रा के लिए लालपेडुई रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को सौंप दिया था। भारत संघ बनाम रीना देवी 1 के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि प्रामाणिक यात्री होने का प्रारंभिक बोझ हटा दिया गया है और जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों पर स्थानांतरित कर दी गई है जिन्हें उनके द्वारा नहीं हटाया गया है। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं। यू. ओ. आई. बनाम राधा यादव 2 के फैसले के आलोक में यह आग्रह किया जाता है क्योंकि मृतक के प्रामाणिक यात्री होने की अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु साबित होती है, मुआवजे की पर्याप्त राशि प्रदान की जा सकती है। 8. कॉन्ट्रा के अनुसार, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दो आवश्यक तत्व हैं जिन्हें सख्त मापदंडों पर साबित करने की आवश्यकता है; पहला मृतक एक 'वास्तविक यात्री' है और दूसरा एक 'अप्रिय घटना' की घटना है। दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, वे तत्व सिद्ध नहीं पाए गए हैं, इसलिए वर्तमान अपील को खारिज किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन पर, विशेष रूप से अध्याय XIII जो दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेलवे प्रशासन के दायित्व से संबंधित है। धारा 123 (सी) "अप्रिय घटना" को परिभाषित करती है। खंड (2) के अनुसार, यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी भी यात्री का दुर्घटनावश गिरना एक अप्रिय घटना होगी। धारा 124 ए के अनुसार, रेलवे प्रशासन अप्रिय घटना के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जब रेलवे के काम करने के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, यह उस यात्री को हकदार बनाएगा जो घायल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। दावे को नुकसान की वसूली के लिए बनाए रखा जा सकता है, और कुछ भी होने के बावजूद

एफ.

जी.

1 (2019) 3 एससीसी 572 2 (2019) 3 एससीसी 410 ए

एच.

405

कामुकायी और ओआरएस. बनाम. भारत और ओआरएस का संघ। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

किसी अन्य कानून में निहित रेलवे ऐसी अप्रिय घटना के लिए निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 'यात्री' के बारे में स्पष्ट करने वाले उक्त खंड के स्पष्टीकरण में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसने किसी भी तारीख को यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्रा करने के लिए वैध टिकट या वैध प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा है और वह किसी अप्रिय घटना का शिकार हो जाता है।

बी.

10. रीना देवी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने रेलवे परिसर में एक यात्री का शव मिलने पर सबूत के बोझ को समझाया है। उक्त मुद्दे का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने राज कुमारी बनाम भारत संघ 3 मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले और गुरचरण सिंह बनाम भारत संघ 4 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों, जेटी नागा लक्ष्मी पार्वती बनाम भारत संघ मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों पर भी विचार किया है।

सी.

कामरुन्निसा बनाम भारत संघ पैरा 29 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया -

“इस प्रकार हमारा मानना है कि रेलवे परिसर में केवल एक शव की उपस्थिति यह मानने के लिए निर्णायक नहीं होगी कि घायल या मृतक एक प्रामाणिक यात्री थे जिसके लिए मुआवजे का

दावा किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे घायल या मृतक के साथ टिकट की अनुपस्थिति इस दावे को नकार नहीं देगी कि वह एक प्रामाणिक यात्री था।प्रारंभिक भार दावेदार पर होगा जिसे प्रासंगिक तथ्यों का एक हलफनामा दाखिल करके हटाया जा सकता है और बोझ तब रेलवे पर स्थानांतरित हो जाएगा और इस मुद्दे का निर्णय दिखाए गए तथ्यों या उपस्थित परिस्थितियों पर किया जा सकता है।इसे पाए गए तथ्यों के आधार पर एक मामले से दूसरे मामले में निपटना होगा।इस संबंध में कानूनी स्थिति तदनुसार समझाई जाएगी।”

डी.

ई.

11. उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और दावे न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेख पर रखी गई दलीलों और सामग्री के आधार पर, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या विकृत हैं।

एफ.

12. दी गई सामग्री के अनुसार, घटना की प्राथमिकी रेलवे पुलिस स्टेशन, करूर द्वारा सुबह 10 बजे 27.9.2014 पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, यह पता चला है कि 27.9.2014 पर, मृतक के शिकायतकर्ता बेटे मणिकंदन (AW1) ने लालपेट्टई रेलवे स्टेशन पर लालपेट्टई से करूर के लिए इरोड पैसेंजर ट्रेन का टिकट खरीदा था।

जी.

3 1992 एससीसी ऑनलाइन एमपी 96 4 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 101 5 2011 एससीसी ऑनलाइन एपी 828 6 (2019) 12 एससीसी 391

एच.

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

और उसे अपने पिता मुचामी @मुथुसामी को दे दिया, जो अपने चिकित्सा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल, करूर जा रहे थे।सुबह लगभग 9 बजे, उन्हें अपने चाचा अयप्पन से जानकारी मिली कि मृतक महादनापुरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सिर काटने और दाहिने हाथ को काटने के साथ गिर गया था।जाँच अधिकारी द्वारा उसी दिन जाँच रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया गया था जिनके तहत दुर्घटना हुई थी, उससे संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:“मृतक मुचामी @मुथुसामी आयु 50/14, पुत्र मुक्कन, कोडिक्कल स्ट्रीट, लालपेट्टई, अपने पैर के घाव का चिकित्सा उपचार करने के लिए सुबह साढ़े

आठ बजे अपने बेटे मणिकंदन और अपने बेटे के साथ लालपेट्टई रेलवे स्टेशन आए और मृतक के लिए लालपेट्टई से करूर की यात्रा करने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा और उन्होंने टिकट प्राप्त किया और इरोड पैसेंजर ट्रेन से त्रिची की यात्रा की। जब ट्रेन महादनापुरम रेलवे स्टेशन पर आई तो मृतक ट्रेन के डिब्बे से नीचे गिर गया और ट्रेन में उलझ गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका सिर काट दिया गया, हाथ काट दिया गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।”13. सिविल सहायक सर्जन, सरकारी मुख्यालय अस्पताल, करूर द्वारा उसी दिन पोस्टमार्टम किया गया था, अर्थात् 27.9.2014 और डॉक्टर ने मृत्यु के कारण के बारे में निम्नलिखित राय दी: “ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 4 से 8 घंटे पहले सदमे और रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों को चोट लगने और सिर के सिर काटने से हुई होगी।”

बी.

सी.

डी.

ई.

14. अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और निष्कर्ष इस प्रकार हैं: “इस मामले में मैंने परिस्थितिजन्य गवाहों से पूछताछ की। उन्होंने वही बयान दिया जो उन्होंने उप-निरीक्षक के सामने दिया था, इसलिए मैं अलग से कोई बयान दर्ज नहीं कर रहा हूँ। घटना स्थल के गवाह के साथ की गई जांच के अनुसार, पंचायती गवाह से पूछताछ करें, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ पूछताछ के अनुसार मृतक मुचामी @मुथुसामी, 50/14, पुत्र मुक्कन, कोडिक्कल स्ट्रीट, लालपेट्टई, कृष्णरायपुरम-टीके, करूर-डीटी घटना की तारीख को अपने पैर पर घाव के चिकित्सा उपचार के लिए करूर जीएच जाते थे और अपने बेटे के साथ साइकिल से स्टेशन आते थे और उनके बेटे ने टिकट खरीदा और उसे ट्रेन में त्रिची से करूर भेज दिया और अपनी नौकरी पर चले गए। ट्रेन में यात्रा कर रहा मृतक Muchamy@Muthusamy महादनापुरम रेलवे स्टेशन पर आया वह ट्रेन से नीचे गिर गया, सिर का सिर कटा हुआ था, दाहिना हाथ ए

एफ.

जी.

एच.

407

कामुकायी और ओआरएस. बनाम. भारत और ओआरएस का संघ। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

अत्यधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मृतक की मृत्यु एक "आकस्मिक मृत्यु" है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मामला खत्म हो जाता है।”

15. दक्षिण रेलवे ने रेलवे यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच का तरीका) नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम, 2003") के नियम 7 (2) के तहत दिनांक 7.6.2017 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में स्टेशन मास्टर, महादनापुरम को सूचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहने के अलावा कि यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, अप्रिय घटना की घटना से इनकार नहीं किया गया है। उक्त रिपोर्ट में, जांच का अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार बताया गया था:

बी.

सी.

“पूछताछ से पता चलता है कि 27.9.2014 पर, मृतक चिकित्सा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल, करूर जा रहा था और टी. नं. 56841 पास (उदा. टीपीजे-ईडी) लालपेट्टई से करूर तक। जब उक्त ट्रेन अपने निर्धारित ठहराव के बाद जा रही थी, तो मृतक नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।”

डी.

16. जाँच के उक्त निष्कर्ष को डी. रविशंकर, स्टेशन मास्टर, तंजौर के बयान पर विचार करने के बाद दर्ज किया गया था, जो 27.9.2014 पर महादनापुरम रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। उनके बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 27.09.2014 पर ट्रेन संख्या 56841 08 बजे महादनापुरम पहुंची: 43 घंटे और 08 बजे खाना: 44 घंटे। प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते समय कोच संख्या 04446 में एसीपी के कारण इसे रोक दिया गया था। जब उन्होंने उक्त कोच में भाग लिया, तो उन्होंने देखा कि लगभग 50 वर्ष की आयु का एक पुरुष व्यक्ति पटरी पर भाग गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, डी. रविशंकर के बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कोच संख्या 04446 में चैन खींचने के कारण, उन्होंने देखा कि मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। जाँच रिपोर्ट के उक्त तथ्य निष्कर्षों को देखते हुए, जो जाँच रिपोर्ट और रेलवे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, त्रिची की अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद है, इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि किसी अन्य सामग्री के अभाव में अप्रिय घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

17. उक्त जांच रिपोर्ट को डी. आर. एम. द्वारा 7.6.2017 पर स्वीकार कर लिया गया था। एफ. आई. आर., जाँच रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और नियम, 2003 के नियम 7 के तहत तैयार की गई जाँच रिपोर्ट के आरोपों के अवलोकन पर, एक अप्रिय घटना के बारे में आरोप, जैसा कि दावा याचिका में कहा गया है, पूरी तरह से स्थापित है और मृतक के बेटे मणिकंदन-एडब्ल्यू 1 की गवाही द्वारा समर्थित है। इसलिए, इस संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष

ई.

एफ.

जी.

एच.

408

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय जांच के दस्तावेजों और डी. आर. एम. द्वारा 7.6.2017 पर स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना हैं और इसलिए ऐसे निष्कर्ष विकृत और निर्धारित हैं।¹⁸ अब, इस मुद्दे पर लौटते हुए कि क्या मृतक एक प्रामाणिक यात्री था? इस संबंध में, मृतक के बेटे एडब्ल्यू¹-मणिकंदन का मौखिक बयान, जिसने लालपेड्डई से करूर की यात्रा के लिए एक वैध ट्रेन टिकट प्राप्त किया और उसे मृतक को सौंप दिया, रिकॉर्ड में है। ए. डब्ल्यू. 1 के बयान के अनुसार, दावा याचिका में किए गए कथनों की गवाही दी गई है और यहां तक कि जिरह में भी उन्होंने दोहराया है कि मृतक के लिए लालपेड्डई से करूर तक का टिकट रुपये की राशि में खरीदा गया था। 10/- और उसे करूर जाने के लिए स्टेशन पर भेज दिया। मृतक महादनापुरम रेलवे स्टेशन पर गिर गया। दावा याचिका के उक्त कथन और स्टेशन मास्टर डी. रविशंकर के बयान को घटना की तारीख पर पूछताछ अधिकारी द्वारा तैयार की गई पूछताछ रिपोर्ट यानी 27.9.2014 और जांच अधिकारी, रेलवे पुलिस स्टेशन त्रिची द्वारा 14.11.2014 पर तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट से समर्थन मिलता है। उक्त रिपोर्टों को दिनांकित 7.6.2017 जांच रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है। अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, प्रारंभिक बोझ कि मृतक यात्री के पास एक वैध टिकट था, उक्त तथ्य को गलत साबित करने के लिए रेलवे प्रशासन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ भी नहीं रखा गया है या रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि रेलवे प्रशासन ने मृतक यात्री के साथ वैध रेलवे टिकट नहीं होने का बोझ उठाया है, सिवाय इसके कि वसूली के दौरान टिकट नहीं मिला था। किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, रेलवे प्रशासन निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि रीना देवी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह उचित संदेह से परे साबित होता

है कि मृतक मुचामी @मुथुसामी की मृत्यु एक यात्री ट्रेन संख्या 5684 में यात्रा करते समय हुई एक अप्रिय घटना में हुई थी और वह एक प्रामाणिक यात्री थे। दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल रूप से दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष विकृत हैं, इसलिए निर्धारित किए गए हैं। हमारे विचार में, रेलवे अधिनियम की धारा 124 ए और रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1990 में निहित प्रावधानों के अनुसार, अपीलार्थियों मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।

जी.

एच.

409

कामुकायी और ओआरएस. बनाम. भारत और ओआरएस का संघ। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दावेदारों को मुआवजे की मांग करने का हकदार माना जाता है, लेकिन सुनवाई के दौरान, यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि दुर्घटना की तारीख के बाद और 25.7.2016 पर दावा याचिका दायर करने के बाद, मुआवजे के नियम, 1990 में W. E. F. 01.01.2017 में संशोधन किया गया था। इसलिए, संशोधित नियमों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा रीना देवी (उपर्युक्त) के मामले में विचार किया गया था, जिसमें पैराग्राफ 18 और 19 में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

बी.

“18. विद्वान न्यायमित्र ने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख विद्वान है

रमन आयरन फाउंड्री और केसोरम इंडस्ट्रीज में प्रस्तुत करने के लिए कि

लागू मुआवजे की राशि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि देय राशि केवल उस दिन है और पहले की नहीं। केसोरम इंडस्ट्रीज में, सवाल यह था कि संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत "शुद्ध संपत्ति" की गणना करने के उद्देश्यों के लिए कर के भुगतान के प्रावधान को उक्त अधिनियम की धारा 2 (एम) के अर्थ के भीतर "बकाया ऋण" के रूप में कब माना जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "ऋण" भुगतान करने के लिए बाध्य था। हालाँकि, आकस्मिकता पर देय राशि तब तक "ऋण" नहीं बन जाती जब तक कि उक्त आकस्मिकता नहीं हो जाती। कर का भुगतान करने की देनदारी इस तरह के कर की मात्रा निर्धारित होने पर उत्पन्न होती है। लेकिन जब कर की दर का पता लगाया जा सकता है, तो राशि को उस वर्ष के लिए ऋण के रूप में माना जा सकता है जिसके लिए कर विचाराधीन लेखा वर्ष के दौरान मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए देय है। इस निर्णय के अनुपात में उस सिद्धांत के साथ कोई टकराव नहीं है जो थझाथे पुरयिल सराबी में प्रस्तावित किया गया है कि वर्तमान संदर्भ में

मुआवजे का अधिकार दुर्घटना की तारीख को उत्पन्न होता है। रमन आयरन फाउंड्री में, सवाल यह था कि क्या बिना मुआवजे के नुकसान का दावा तब तक "ऋण" को जन्म नहीं देता जब तक कि देयता निर्धारित नहीं हो जाती। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक देयता का न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता, तब तक बिना ऋण चुकाये हुए नुकसान के दावे से कोई ऋण उद्भूत हुई है नहीं होता है। इस निर्णय से भी यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि मुआवजे का दायित्व, वर्तमान संदर्भ में, केवल उसके निर्धारण पर उत्पन्न होता है, न कि दुर्घटना की तारीख पर। चूंकि यह माना गया है कि ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए जिस आधार पर राठी मेनन आधारित हैं, वह बदल गया है। हमारा विचार है कि वर्तमान संदर्भ में कानून यह माना जाना चाहिए कि देयता दुर्घटना की तारीख को उपार्जित होगी और उस तारीख को लागू राशि वसूली योग्य राशि होगी, लेकिन दावेदार को दुर्घटना की तारीख से भुगतान तक उस दर पर ब्याज मिलेगा जिसे समय-समय पर उचित और उचित माना जाए। इस संदर्भ में, मोटर दुर्घटना दावे में लागू ब्याज की दर

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

410

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

मामलों को उचित और निष्पक्ष माना जा सकता है। एक बार ब्याज की अवधारणा पेश किए जाने के बाद, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के सिद्धांतों को निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है और

प्रताप नारायण सिंह देव में चार-न्यायाधीशों की पीठ पूरी तरह से लागू होगी।

जहां भी यह पाया जाता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख को लागू मुआवजे की संशोधित राशि दुर्घटना की तारीख को ब्याज के साथ मुआवजे की निर्धारित राशि से कम है, दोनों में से अधिक राशि लाभकारी कानून के सिद्धांत पर दी जानी चाहिए। वर्तमान विधान निश्चित रूप से लाभकारी विधान का एक हिस्सा है।

बी.

19. तदनुसार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दुर्घटना की तारीख को लागू मुआवजे का भुगतान ब्याज के साथ किया जाएगा, जिसे समय-समय पर दुर्घटना के दावे के मामलों की तरह ही उचित माना जा सकता है। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख को निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार दोनों में से अधिक राशि का हकदार होगा। यह आदेश उन पुरस्कारों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही अंतिम हो चुके हैं और जहां ऐसे पुरस्कारों को चुनौती देने की सीमा समाप्त हो गई है, यह आदेश अपने आप में देरी को माफ करने का आधार नहीं होगा।

सी.

डी.

राठी मेनन और कलंदी चरण साहू में टकराव दिखाई दे रहा है

तदनुसार समझाया गया है। प्रताप नारायण सिंह देव मामले में चार-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला इस विषय पर आधारित है और वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से लागू होता है। दुर्घटना की तारीख को लागू मुआवजे को उचित ब्याज के साथ दिया जाना चाहिए और लाभकारी कानून के अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए, यदि न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख पर प्रदान किया गया मुआवजा ब्याज के साथ अपरिशोधित राशि से अधिक है, तो दोनों में से अधिक राशि दी जानी चाहिए।”

ई.

एफ.

21. उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा राधा यादव (उपरोक्त) के मामले में आगे समझाया गया था, प्रासंगिक पैरा 11 इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है: “11. इस मामले में उठाए गए मुद्दे को वास्तव में किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे विचार में, रीना देवी में इस न्यायालय का निर्णय बहुत स्पष्ट है। इस न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वह यह है कि दुर्घटना की तारीख को उचित ब्याज दर के साथ देय मुआवजे की राशि की गणना पहले की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि पुरस्कार की तारीख को निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार इन दो राशियों में से अधिक राशि का हकदार होगा। इसलिए, यदि दायित्व संशोधन से पहले उत्पन्न हुआ था ए

जी.

एच.

इसमें मूल आंकड़ा अनुसूची के अनुसार होगा जो संशोधन से पहले मौजूद था और ऐसे मूल आंकड़े पर ब्याज की उचित दर की गणना की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि और पुरस्कार की तारीख को अनुसूची में निर्धारित राशि के बीच कोई अंतर है, तो मुआवजे का माप दो अंकों में से अधिक होगा। उदाहरण के लिए, संशोधन से पहले हुई दुर्घटना में मृत्यु के मामले में, मूल आंकड़ा रु. 4,00,000-होगा। यदि, उचित ब्याज दर लागू करने के बाद, अंतिम आंकड़ा रुपये से कम होना था, जिसे संशोधन के माध्यम से लाया गया था, तो दावेदार रुपये का हकदार होगा। हालाँकि, यदि ब्याज की दर के साथ मूल मुआवजे की राशि रु. 8,00,000 की राशि से अधिक थी-तो मुआवजा रु. 8,00,000-से अधिक के आंकड़े के संदर्भ में होगा। विचार यह है कि जहां तक संभव हो, संशोधन का लाभ उठाया जाए। इस प्रकार, हमारे अनुसार, मामला स्पष्ट है। इस मुद्दे को और अधिक स्पष्टीकरण या विस्तार की आवश्यकता नहीं है।”

बी.

सी.

डी.

22. उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा मामले में की गई है

भारत संघ बनाम दिलीप और अन्य **7.**

23. तदनुसार और उपरोक्त चर्चा के अनुसार हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय और दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 26.03.2021 के विवादित फैसले को भी अपास्त करना कर देते हैं। नतीजतन, दावा आवेदन की अनुमति है। अपीलार्थियों एक लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। 4,00,000-दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज दर लागू करने के बाद, यदि अंतिम आंकड़ा रुपये से कम है। 8,00,000-, तब अपीलार्थियों रुपये के हकदार होंगे। 8,00,000-। उत्तरदाताओं द्वारा मुआवजे की राशि को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

ई.

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

7 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 2119

एच.

